

भारत में चीनी का प्रोडक्शन 41.35 लाख टन तक पहुंचा; NFCSF की सरकार से 10 LMT और चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत देने की अपील

– By Bhagyashree Rhatwal

(चीनीमंडी कॉम; मुंबई: दिसम्बर 01, 2025)

नई दिल्ली : भारत में 2025-26 सीज़न के लिए गन्ने की पेराई का काम तेज़ हो गया है। 30 नवंबर, 2025 तक, 486 लाख मीट्रिक टन (LMT) गन्ने की पेराई हो चुकी है (पिछले साल के 334 LMT के मुकाबले), और 41.35 LMT चीनी का उत्पादन हुआ है (पिछले साल के 27.60 LMT के मुकाबले)। नेशनल फेडरेशन ऑफ़ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज़ लिमिटेड (NFCSF) के डेटा के मुताबिक, नवंबर के आखिर तक औसत चीनी रिकवरी 8.51% है, जबकि पिछले साल इसी तारीख को यह 8.27% दर्ज की गई थी।

नॉर्मल मॉनसून और वापस आती बारिश खत्म हो गई है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ इलाकों को छोड़कर, जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, गन्ना पेराई का काम अभी पूरे ज़ोरों पर है। NFCSF के अनुसार, इस समय, मौजूदा सीज़न (सितंबर 2026) के आखिर में कुल चीनी उत्पादन 350 LMT होने का अनुमान है। साइकिल-1, एथेनॉल एलोकेशन के हिसाब से, लगभग 35 LMT चीनी एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने की उम्मीद है, जिससे 315 LMT का नेट चीनी प्रोडक्शन रिकॉर्ड होगा, जिसमें मुख्य योगदान देने वाले राज्यों में महाराष्ट्र-110 LMT, उत्तर प्रदेश-105 LMT, कर्नाटक-55 LMT, और गुजरात-8 LMT होंगे।

इसमें से, अनुमानित घरेलू खपत 290 LMT है, और 50 LMT के शुरूआती स्टॉक की गिनती करने पर, चीनी मिलों के गोदामों में लगभग 75 LMT का बैलेंस बचेगा। इससे बहुत ज्यादा फंड ब्लॉक हो जाएगा और ब्याज का बोझ बढ़ेगा। इसलिए, NFCSF ने भारत सरकार से एक्सपोर्ट के लिए अतिरिक्त 10 LMT (पहले से घोषित 15 LMT के अलावा) की अनुमति देने का अनुरोध किया है। इस कदम से न सिर्फ़ घरेलू चीनी की कीमतों में मजबूती आएगी, बल्कि इससे घरेलू बाजार का माहौल भी बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय चीनी की थोड़ी-बहुत खेप ग्लोबल बाज़ार में आ रही है, इसलिए अभी की कम अंतरराष्ट्रीय चीनी की कीमतों पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा।

पूरा चीनी सेक्टर चीनी के मिनिमम सेलिंग प्राइस (MSP) में लंबे समय से रुके हुए बदलाव को लेकर उलझन और अनिश्चितता का सामना कर रहा है। NFCSF ने एक रिलीज में कहा कि, कर्नार्जन कॉस्ट, फाइनेशियल ओवरहेड्स, ब्याज का बोझ, होलिंग कॉस्ट और मिलों को नॉर्मेटिव रिटर्न में काफी बढ़ोतरी के बावजूद, पिछले छह सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। NFCSF के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन पाटिल ने कहा, मौजूदा MSP को बदलकर तुरंत Rs. 41 प्रति kg करने की ज़रूरत है। यह ध्यान देने वाली बात है कि, ब्राज़ील और थाईलैंड जैसे बड़े गन्ना उगाने वाले देशों में किसानों को दिया जाने वाला रेवेन्यू शेयर लगभग 60-65% है, बिना किसी मिनिमम गारंटी (FRP) के, जबकि भारत में, चीनी MSP Rs. 41 प्रति kg को ध्यान में रखते हुए भी यह 75-80% बैठता है।"

हर्षवर्धन पाटिल ने आगे कहा, इस मामले को देखने का एक और नज़रिया रंगराजन कमेटी की सिफारिश पर आधारित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकारों ने कानून पास किया है कि चीनी मिलों किसानों के साथ फायदा शेयर करेंगी। इस तरह, लगभग 75% फायदा किसानों को जाएगा और 25% चीनी मिलों के पास रहेगा। इससे सीधे तौर पर 5 करोड़ छोटे और कम आय वाले गन्ना किसानों को फायदा होगा।

NFCSF के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नाइकनवरे ने कहा, भारत में 513 डिस्टिलरी हैं जिनकी कुल डिस्टिलेशन कैपेसिटी 1953 करोड़ लीटर/साल है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा 281 डिस्टिलरी का रहा है। मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 838 करोड़ लीटर/साल है, 210 ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 980 करोड़ लीटर/साल है और 22 और डुअल फीड बेस्ड डिस्टिलरी जिनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 135 करोड़ लीटर/साल है।

इस बड़े पैमाने पर इन्वेस्टेड डिस्टिलेशन कैपेसिटी के उलट, शुगर सेक्टर के लिए एथेनॉल एलोकेशन सिर्फ़ 288.60 करोड़ लीटर रहा है, जबकि बाकी 759.80 करोड़ लीटर ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी को दिया गया है। Cycle 1 के एलोकेशन में इस बड़ी गड़बड़ी को न सिर्फ़ ठीक करने की ज़रूरत है, बल्कि शुगर बेस्ड एथेनॉल की कीमतों में लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा बढ़ोतरी भी समय की ज़रूरत है, जिसके लिए हम, NCSF में, संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार फॉलो-अप कर रहे हैं।
